भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1319

दिनांक 09.02.2022 को उत्तर देने के लिए

अंतिम छोर तक सुपुर्दगी

1319. **श्री रतन लाल कटारिया:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंतिम छोर तक सुपुर्दगी तथा सर्वोत्कृष्ट और समावेशी विकास मॉडल को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की जनोन्मुखी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डिजिटल इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाया है और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी, हां।

(ख) देश में अंतिम छोर तक सुपुर्दगी और सर्वोत्कृष्ट तथा समावेशी विकास मॉडल को प्राथमिकता दी गई है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रमुख पहलों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है:

1. **आधार** - यह भारत के निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान करता है। इसने 1.32 बिलियन लोगों को नामांकित किया है। इसने अब तक 66.7 बिलियन ई-ऑथेंटिकेशन और 11 बिलियन ई-नो योर कस्टमर्स (केवाईसी) की सेवा प्रदान की है।

2. **जन धन योजना** - यह प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है। इसने 44.51 करोड़ लाभार्थियों को बैंक खाते की सुविधा प्रदान की है। लाभार्थी के खातों में ₹157,455 करोड़ की राशि शेष हैं। इस योजना के तहत 1.26 लाख बैंक मित्र काम कर रहे हैं।

3. **मोबाइल और इंटरनेट** - भारत दूरसंचार और मोबाइल के लिए जीवंत स्थान है। देश में कुल 117 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। इनमें से 63.8 करोड़ शहरी क्षेत्र से और 52.8 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र से हैं। कुल 83.4 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं।

4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) - डीबीटी प्लेटफॉर्म सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभ के अंतरण को सुगम बना रहा है। डीबीटी के माध्यम से कुल 20.9 लाख करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है। यह प्लेटफॉर्म 54 मंत्रालयों में 312 योजनाओं के साथ एकीकृत है। प्लेटफॉर्म से 2.2 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ हुआ है।

5**. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** - सीएससी दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा ई-सेवा वितरण केंद्र है। सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं। 4.47 लाख सीएससी हैं और इनमें से 3.48 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचालनाधीन हैं। यह 350+ सेवाओं का पोर्टफोलियो प्रदान करता है। ग्रामीण स्तर की 73,403 महिला उद्यमी हैं। सीएससी 2.39 लाख ग्रामीण ई-स्टोर भी संचालित करते हैं, जो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ई-कॉमर्स जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

6**. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)** - पीएमजीडीआईएसएचए डिजिटल साक्षरता योजना है जिसमें वित्तीय साक्षरता शामिल है। पीएमजीडीआईएसएचए का लक्ष्य प्रत्येक परिवार/घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। वित्तीय साक्षरता के एक भाग के रूप में, डिजिटल भुगतान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएमजीडीआईएसएचए के तहत 5.52 करोड़ अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, 4.68 करोड़ अभ्यर्थी प्रशिक्षित हैं, और 3.47 करोड़ अभ्यर्थी प्रमाणित हैं।

7. **डिजिलॉकर** - यह अग्रणी पेपरलेस पहलों में से एक है। इसके 9.2 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। यह 4.86 बिलियन जारी किए गए दस्तावेज़ प्रदान करता है। इसमें 1692 जारीकर्ता और 349 अनुरोधकर्ता संगठन शामिल हैं।

8. **यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)** - इसे सरकार द्वारा एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं की पेशकश करने के लिए विकसित किया गया है। यह 271 विभागों से 1375 सरकारी सेवाएं (केंद्र से 659 + 32 राज्यों से 716) और 20,527 बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करता है। इसने 401+ लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 27 लाख दैनिक लेनदेन की सेवा प्रदान की है।

9. **माईजीओवी** - यह सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव प्लेटफॉर्म है। यह नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संचार को सुकर बनाता है और डिजाइन, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद के आकलन से सरकारी योजनाओं पर विचार-विमर्श करने और सुधारने के लिए क्राउड सोर्सिंग का उपयोग करता है। इसके 2.25 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। माईजीओवी पर 11.6 लाख से अधिक प्रस्तुत किए गए कार्यों को संभाला गया है। माईजीओवी हेल्पडेस्क व्हाट्सएप पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम चैटबॉट सेवा प्रदाता है। यह कोविड से संबंधित जानकारी, कोविड टीकाकरण अपाइंटमेंट, आधार, स्थायी खाता संख्या (पैन) और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी डिजिलॉकर सेवाएं प्रदान करता है। इसने 7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 29 करोड़ उपयोगकर्ता संदेशों से संबंधित सेवा प्रदान की है।

10. **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)** - यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अग्रणी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, **यूपीआई** को 282 बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है और जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 तक 71.6 ट्रिलियन रुपये के 38.74 बिलियन लेनदेन को प्रोसेस किया गया है।

11. **ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा)** - दीक्षा प्लेटफॉर्म शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम से संबंधित आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। यह

6209 पाठ्यक्रम प्रदान करता है और अब तक 453 करोड़ शिक्षण सत्रों की सुविधा प्रदान कर चुका है।

12. **स्वयं प्रभा** - स्वयं प्रभा 34 डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) चैनलों का एक समूह है जो जीसैट -15 उपग्रह का उपयोग करके 24X7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। प्रत्येक दिन, कम से कम (4) घंटे के लिए नई सामग्री होगी जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के लिए समय चुन सकेंगे। सामग्री नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (एनपीटीईएल), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), शैक्षिक संचार के लिए सहायता संघ (सीईसी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा प्रदान की जाती है। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केंद्र वेब पोर्टल का रखरखाव करता है।

13. **आयुष्मान भारत** - यह दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है जो समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए लक्षित है। इस योजना ने 17.35 करोड़ ई-कार्ड की पेशकश की है और 2.6 करोड़ अस्पताल में दाखिले को सुकर बनाया है।

14. **एम-किसान** - एम-किसान के माध्यम से मोबाइल आधारित कृषि और सलाहकार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उपयोग की जाने वाली मोबाइल/वेब प्रौद्योगिकियां पुश एसएमएस, पुल एसएमएस, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस), मोबाइल ऐप और वेबसाइट हैं। यह किसानों को अपनी कृषि उपज में सुधार के साथ-साथ कृषि स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने के लिए सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद करता है। 5.13 करोड़ किसान एम-किसान प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। एम-किसान के जरिए 2,462 करोड़ एसएमएस भेजे जा चुके हैं। एम-किसान के माध्यम से 4.36 लाख परामर्श (एजवाइज़री) भेजे जा चुके हैं।

15. **ई-संजीवनी** - यह राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवा है जिसका उद्देश्य रोगियों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अस्पताल में डॉक्टर और अपने घर की सीमा में मरीज के बीच सुरक्षित और संरचित वीडियो-आधारित नैदानिक परामर्श को सक्षम बनाया जा रहा है। इसने 2.78 लाख से अधिक परामर्श घंटों को सुकर बनाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) केंद्र सरकार की जनोन्मुखी योजनाओं का लाभ जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। इसका ब्योरा ऊपर बिंदु (ख) में देखा जा सकता है।

(ङ) जी, हां।

(च) डिजिटल इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाया है और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। युवाओं के लिए अवसरों और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पहलों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है:

1. **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)-** यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अग्रणी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, यूपीआई को 282 बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है और जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 तक 71.6 ट्रिलियन रुपये के 38.74 बिलियन लेनदेन को प्रोसेस किया गया है।

2. **भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)** - बीबीपीएस को सभी बिल भुगतानों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में चालू किया गया है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, बीबीपीएस को 20,374 बिलर्स के साथ एकीकृत किया गया है और जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 तक 959 ट्रिलियन रुपये के 562.31 मिलियन लेनदेन को प्रोसेस किया गया है।

3. **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क** - यह एक राष्ट्र एक कर प्लेटफॉर्म को सुकर बना रहा है। प्लेटफॉर्म पर 1.34 करोड़ पंजीकृत करदाता हैं। पोर्टल (आयात पर आईजीएसटी को छोड़कर) के माध्यम से 41.23 लाख करोड़ रुपये के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से 242.69 करोड़ से अधिक ई-वे बिल और 1492 करोड़ इनवॉइस अपलोड किए गए हैं।

4. **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (पीएलआई) में प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना** - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कई प्रदर्शन-से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। भारत में 76,000 करोड़ रुपये (>10 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय पर सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम की मंजूरी के साथ, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सब-असेंबली, तैयार माल सहित आपूर्ति श्रृंखला के हर हिस्से के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। सब-असेंबली और तैयार माल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई, स्पेक्स योजना और रूपांतरित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लिए पीएलआई के तहत 55,392 करोड़ रुपये (7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की प्रोत्साहन सहायता को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं, जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण में ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में ये पीएलआई योजनाएं देश में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और कुशल रोजगार पैदा करने में सहायक हैं।

5. **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस** (जेम)-जेम सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ा रहा है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सुगमता प्रदान करने के लिए ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के साधन प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म पर 57,000 से अधिक खरीदार संगठन और 37 लाख विक्रेता शामिल हैं। जेम में 45.6 लाख से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं। इसने 1.88 लाख करोड़ रुपये के कुल 88.9 लाख ऑर्डर प्रोसेस किए हैं। इसमें 747,839 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसइ) विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं और उन्हें कुल ऑर्डर का 56.28% (अर्थात 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का ऑर्डर मूल्य प्राप्त हुआ है।

6. **फ्यूचर स्किल्स प्राइम** - इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10 उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक-चेन, 3 डी प्रिंटिंग, संवर्धित वास्तविकता/आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर) साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आदि में आईटी पेशेवरों के कौशल को उनकी आकांक्षाओं और योग्यता के अनुरूप निरंतर बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) केंद्रों का अखिल भारतीय नेटवर्क भी मिश्रित-शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे शहरों और दूरदराज के स्थानों में इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

***